

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 77]

नई विल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 1991/फाल्गुन 8, 1912

No. 77) NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 1991/PHALGUNA 8, 1912

इ.स. भाग में भिल्म पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अजग संकालन के काप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक जिकायत और पंजान मंत्रालय

(कार्मिक भौर प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई विल्ली, 26 फरवरी, 1991

सा. का. ति. 99(अ):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्रक्षिकरण प्रशिवियम, 1985 (1985 का 13) की घारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (च), (क) तथा (ज) तथा धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा प्रवत्त शिक्तरों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक प्रधिकरण (क्रिया-विधि) नियमावली, 1987 में और आगे संशोधन करते हुए एसव्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातु:—

- 1 (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक ग्रधिकरण (क्रिया-विधि) मंशोधन नियमावली, 1991 होगा।
- (2) में सरकारी राजपक्ष में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रियाविधि) नियमावली, 1987 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 5 में,

- (i) उप नियम (4) में, खण्ड (ख) विलोपित किया आएगा;
- (ii) उप नियम (5) विलोपित किया जाएगा।
- 3. उक्त निथमों के नियम ii के उपनियम (i) में, खण्ड (iv) के लिए, निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, प्रचीतु:—
 - "(iv) उसी विभाग के संबंधित कार्यासयाध्यक्ष के माध्यम से।"
- 4. उस्त नियमों के नियम 12 में, उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा आएगा, ग्रंथीत्:—
- "(6) प्रधिकरण संबंधित पार्टियों को उसी ढंग से दलीलों में संशो-धन की प्रमुमित दे सकता है" जैसे कि सिबिल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के निधम 17 के आदेश 6 के प्रन्तर्गत व्यवस्था की गई है।
- 5. उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया आएगा, भर्थातु:—
- "(2) जहां किसी प्रतिवादी प्रथवा प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रावेदन पर एक पक्षीय सुनवाई की गई हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी प्रथवा

ऐसे प्रतिवादियों द्वारा आवेण की तारीख से 30 विन के भीतर अधिकरण को इस आवेदन को रह करने के लिए आदेश वेने के लिए अधिकरण को आवेदन किया जा सकता है और यदि ऐसा प्रतिवादी अथवा ऐसे प्रतिवादी प्रधिकरण को इस बान के लिए सम्मुख्ट कर वेने हैं कि नोटिस विधिवत् नहीं विया गया था, प्रयवा यह कि उसे अथवा उन्हें मुनवाई के लिए बुलाया गया था इस समय उन्हें किसी प्रयन्ति कारण से रोका गया था तो अधिकरण ऐसी भनी पर जिन्हें वह उजित समझे, प्रतिवादी अथवा प्रतिवादियों के विरुद्ध एक-पक्षीय आवेश को रह किए जाने के आवेश दे सकता है, तथा अवेदन पर कार्यवाही के लिए एक दिन निर्धारिस कर सकता है;

परन्तु भर्त यह है कि जहां भावेदन का एक पक्षीय धावेग ऐसे स्वरूप का हो कि इसे केवल एक प्रतिवादी के विरुद्ध ध्रप्तग नहीं रखा जा सके तो इसे सभी भ्रयता ध्रस्य प्रतिवादियों के विरुद्ध भी भ्रालग रखा जा सकता है।

भौर यह भी कि नियम ii के उप-नियम (8) में शामिल किए गए मामलों में भिधकरण भावेदन के एक पक्षीय शादेश को केवल इस भाषार पर नजर भ्रावज नहीं कर सकता कि यह भावेश किसी प्रतिवादी भणवा प्रतिवादियों को नहीं दिया गया था"।

6. उक्त नियमों के नियम 17 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रति-स्थापित किया आएगा, प्रथात्:----

"17. पुनरीक्षा के लिए आवेदन:---

- (1) पुनरीक्षा के लिए किसी भी याधिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इसे तथा उस झावेश की प्रति को जिसके संबंध में पुनरीक्षा की मांग की गई थी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर दायर न किया जाए।
- (2) पुनरीक्षा के लिए किसी भी यानिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके साथ यथिकित हलेफनामा न लगाया गया हो जिसमें जानकारी—————— अपितार अथवा धरयया तथा उन व्यक्तियों की जानकारी, जिनकी कानूनी सलाह के भाधार पर शपय ली गई है— का स्रोत निर्विष्ट किया गया हो। जहां तथ्य का कोई प्रमाण पन्न विवाद- ग्रस्त हो वहां पुनरोजा याचिका का प्रति हलकनामा भी विधिवत् इप से शपय निया हलफनामा होगा।
- (3) जब तक िक संबंधित पीठ द्वारा ग्रन्थया भादेश न दिया जाए, पुनरीक्षा याचिका का निपटान परिचालन द्वारा ही किया जाएगा, जहां पीठ या तो याचिका को रद्ध कर दे भ्रथवा कोई निर्वेश वे दे तो विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी करना पड़ेगा"
- 7. उक्त नियमों के नियम 29 में खण्ड (X) के स्थान पर निम्न-लिखिल खंड प्रतिस्था।पत किया जाएगा, ग्रायीन).--
 - "(x) श्रावेदन की विचाराधीनता के धीरान मृतक पार्टियों काननी प्रतिनिधियों के स्थानापन्न के लिए मृत्यु की तारीख से 90 दिन के भीतर श्रावेदन प्राप्त करना"।

[सं. ए.-11019/44/87-प्रशा. मधि. एस.एम. सहारियार, डेस्क मधिकारी (प्र.मधि.)

हिंप्पण:---मुख्य नियम विनांक 6-1-1987 की प्रधिसूचना सा.का.नि. सं. 17(ई) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में दिनांक 11 प्रक्तूबर, 1987 की प्रधिसुचना सा.का.नि.सं. 1000 (ई) द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1991

- G.S.R. 99 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (e) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely:—
 - (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1991.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 5 of the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules).
 - i in sub-rule (4), clause (b) shall be omitted;
 - (ii) sub-rule (5) shall be omitted.
- 3. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (1), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(iv) through the concerned head of Office of the same Department."
- 4. In rule 12 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added, namely:—
 - "(6) The Tribunal may permit the parties to amend the pleadings in the same manner as provided under Order 6, Rule 17 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".
- 5. In rule 16 the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:
 - "(2) Where an application has been heard ex-parte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply within 30 days from the date of the order to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served, or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when application was called for hearing the Tribunal may make an order setting aside the ex-parte order as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the application:

Provided that where the exparte order of the application is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:

- Provided further that in cases covered by sub-rule (8) of rule 11, the Tribunal shall not set aside exparte order of an application merely on the ground that it was not served upon a respondent or respondents".
- 6. For rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "17. Application for review:
 - (2) No petition for review shall be entertained unless it is filed within thirty days from the date of receipt and copy of the order of which the review was sought.
 - (2) No petition for review shall be entertained unless it is supported by a duly sworn affidavit indicating therein the source of knowledge—personal or otherwise and also those which are sworn on the basis of the legal advice. The counter affidavit in Review Petition will also be a duly sworn affidavit wherever any averment of fact is disputed.

- (3) Unless ordered otherwise by the Bench concerned a review petition shall be disposed of by circulation where the Bench may either reject petition or direct notice to be issued to the opposite party."
- 7. In rule 29 of the said rules, for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(x) To receive applications within ninety days from the date of death for substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the application."

[No. Λ -11019/44/87- Λ T]

S. M. SAHARIAR, Desk Officer (AT).

NOTE:—The principal rules were published vide Notification G.S.R. No. 17 (E), dated 6-1-1987 and subsequently amended vide Notification G.S.R. No. 1000 (E), dated 11th October, 1987.